www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 5 अप्रैल 2019

दैनिक जागरण
कर्म निराशा की दवा है

वायनाड की पहेली

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद यहां से चुनाव लड़ने के अपने फैसले की एक वजह दक्षिण भारत के साथ खड़े होने का संदेश देना बताया। इस संदेश को सही तरह ग्रहण करना आसान नहीं। क्या राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि अब देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ खड़ा होना दिखने के लिए वहां से चुनाव लड़ना आवश्यक है? सवाल यह भी है कि वह अमेठी के जरिये दक्षिण भारत के साथ खड़े होने का संदेश क्यों नहीं दे सकते थे? समझना कठिन है कि वह उत्तर-दक्षिण की खाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या फिर उसे पाटने का? वायनाड से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने यह भी बयान किया कि वह माकपा के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे-एक शब्द भी नहीं। आखिर ऐसा कहकर वह अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो जब-तब माकपा कार्यकर्ताओं के हिंसक व्यवहार का सामना करते रहते हैं? क्या राहुल गांधी यह कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को माकपा के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के काम-काज से कोई शिकायत नहीं? अगर राहुल गांधी के मन में माकपा के प्रति इतना ही मैत्री भाव उमड़ आया है तो फिर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्या वह पश्चिम बंगाल में भी माकपा और अन्य वाम दलों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे? क्या इसकी अनदेखी कर दी जाए कि वायनाड का चुनावी इतिहास यह कह रहा है कि लोकसभा चुनावों में यहां कांग्रेस की टक्कर माकपा से ही होती रही है? जैसे इन सवालों का कोई जवाब नहीं नजर आता वैसे ही इस सवाल का भी नहीं कि अगर अमेठी से बार-बार चुनाव लड़ने से उत्तर भारत में कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकी तो फिर वायनाड से चुनाव लड़कर दक्षिण भारत में पार्टी को कैसे मजबूती दी जा सकती है? इस तरह के सवाल अमेठी और साथ ही उत्तर भारत के कांग्रेस के समर्थकों को भ्रमित करने का काम करें तो हैरत नहीं।

यह समझ आता है कि अमेठी में चुनौती कठिन होती देखकर राहुल गांधी ने अपने लिए एक सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की तलाश में वायनाड का चयन किया हो, लेकिन उन्हें यह आभास होना चाहिए कि यहां उन्हें कांग्रेस के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन के भरोसे रहना होगा। आखिर ऐसे दल के समर्थन से चुनाव लड़कर वह कांग्रेस के सेक्युलर होने के दावे को मजबूती कैसे दे सकते हैं? निःसंदेह यह पहली बार नहीं जब किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने दक्षिण भारत से चुनाव लड़ा हो। इसके पहले इंदिरा गांधी चिकमगलूर और सोनिया गांधी बेल्लारी से चुनाव लड़ चुकी हैं। राहुल गांधी इनमें से किसी सीट का चयन कर सकते थे। कर्नाटक की सत्ता में तो कांग्रेस साझीदार भी है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले का मूल कारण जानना एक पहेली ही है। कहना कठिन है कि वायनाड के जरिये कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को एक पहेली का जो रूप दिया उससे उसे क्या हासिल होगा?

आइआइटी की पहल

बिहार जैसे राज्यों में हिंदी माध्यम से उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने वाले फिजिक्स के छात्रों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर की मुफ्त शिक्षा की पहल वरदान साबित होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ऑनलाइन सेवा है। गांव-कस्बे या दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र भी अब अपने सवालों का हल जान सकेंगे। शिक्षक का अभाव या कक्षा नियमित न होने की वजह से जो छात्र सवालों का हल जानने के लिए परेशान रहते हैं, इस सेवा से वे लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा, जो व्याख्यान अपलोड किए जाएंगे। फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि फिजिक्स के छात्रों और शिक्षकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए व्याख्यान में ज्यादा से ज्यादा पाठ्यक्रम समाहित होगा। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन निबंधन जरूरी है। निबंधन निःशुल्क है। इसकी प्रक्रिया विश्वविद्यालय या कॉलेजों में संचालित होने वाले क्लास की तरह ही होगी, जिसमें उपस्थिति अनिवार्य होगी। जब छात्र निबंधन कराएंगे तो उन्हें ईमेल पर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। बगैर निबंधन के छात्रों को इस सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा। सॉफ्टवेयर को इस तरह विकसित किया गया है कि छात्र द्वारा व्याख्यान को सुनने की अवधि का भी पता चलेगा। जब तक छात्र पूरे व्याख्यान को नहीं सुन लेता, उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। व्याख्यान सुनने के बाद छात्र अपना सवाल बॉक्स में दर्ज करेंगे। इसका जवाब 24 घंटे के अंदर शिक्षक द्वारा दिया जाएगा। यदि कोई छात्र अपना अनुभव दूसरे छात्रों से साझा करना चाहे तो इस सॉफ्टवेयर में यह सुविधा भी उपलब्ध है। हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र फिजिक्स को समझ सकें और उसका लाभ ले सकें इस उद्देश्य से शुरू की गई सेवा को प्रतिस्पर्धी स्वरूप भी दिया गया है। इस सेवा में जिस निबंधित छात्र की उपस्थिति नब्बे फीसद दर्ज होगी उसे प्रमाणपत्र दिया जाएगा। जो छात्र उम्दा प्रदर्शन करेंगे उन्हें आइआइटी कानपुर में प्रैक्टिकल करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए ऐसे छात्रों को ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था भी निःशुल्क होगी। जाहिर है, कोई छात्र फिजिक्स विषय में विशेषता हासिल करना चाहे तो उसके लिए सारे अवसर उपलब्ध हैं।

सीमित विकल्प वाले आम चुनाव

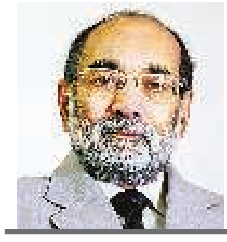

डॉ. एके वर्मा

भारतीय मतदाता लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय नेतृत्व का महत्व समझ चुका है, लेकिन उसके पास चयन के सीमित विकल्प हैं

लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वास्तविक स्थिति 23 मई को मतगणना के बाद स्पष्ट होगी। इस दौरान उन प्रवृत्तियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है जो परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। विपक्षी दलों ने चुनाव मोदी-केंद्रित बना दिया है या तो आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं या उनके खिलाफ। ऐसा बंटवारा कभी साम्यवादी विचारक मार्क्स के बारे में हुआ करता था। ऐसी मान्यता थी कि या तो आप मार्क्सवादी हैं या उसके विरोधी। मार्क्स दार्शनिक विचारक थे, मोदी व्यावहारिक राजनीतिज्ञ हैं। मार्क्स वामपंथी थे। मोदी दक्षिणपंथी हैं पर दोनों उपेक्षितों और वंचितों के लिए चिंतित हैं। राहुल गांधी ने मोदी पर 'सूट-बूट' यानी अमीरों की सरकार होने का आरोप लगाया था और अभी भी यह आक्षेप लगाते हैं कि वह चंद उद्यमियों की चिंता करते हैं। क्या वह सच है? मोदी सरकार द्वारा 2014 में शुरू जनधन योजना के तहत 30 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुलवाने से गरीबों के वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया तेज हुई है। गरीबों की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हुई है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ उनके खाते में सीधे आने लगा है। आम चुनावों का तात्कालिक संदर्भ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की हार और कांग्रेस की जीत है। इससे उत्साहित कांग्रेस ने उप्र में प्रियंका और ज्योदिरादित्य सिंधिया को उतारा। कांग्रेस प्रियंका को 'प्रमोट' कर रही है और उन्हें 'पार्टी-आइकॉन' बनाना चाहती है, लेकिन राजनीति नए दौर में है और 'कॉस्मेटिक-पॉलिटिक्स' का प्रभाव संदिग्ध है। अमेठी और रायबरेली तक में कांग्रेस का जनाधार कमजोर हो चुका है और शायद इसीलिए राहुल को दक्षिण का रुख करना पड़ा। जिनको मोदी नापसंद हैं उनके लिए इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका आकर्षण का केंद्र हो सकती हैं, पर इंदिरा के विपरीत प्रियंका का राजनीति में न तो कोई दखल रहा है, न दिलचस्पी। जनता उनसे क्यों प्रभावित हो?

उप्र में सपा-बसपा गठजोड़ से भाजपा विरोधी माहौल बना जरूर, पर सपा-बसपा अंतर्विरोध और लगभग 40-40 दलीय प्रत्याशियों को टिकट से वंचित करने से साझा उम्मीदवारों के विरुद्ध दोनों दलों में विस्फोटक स्थिति है। मतों के हस्तांतरण की जिस बुनियाद पर गठबंधन बना, वह संकट में है। जहां-जहां सपा प्रत्याशी है वहां दलित मतदाता मोदी को वोट देना चाहता है। जहां बसपा प्रत्याशी है वहां सपा का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और यादव/ओबीसी मतदाता भाजपा की ओर आकर्षित है। जबसे सपा का विघटन हुआ और अखिलेश-शिवपाल का बंटवारा हुआ तबसे सपा का मतदाता पार्टी की धूमिल संभावना देख किसी मजबूत ठौर-ठिकाने की तलाश में है। ऐसी मान्यता है कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देते। 1990 के दशक में मुट्ठी भर मुस्लिम भाजपा को वोट देते थे, लेकिन अब भाजपा का मुस्लिम जनाधार बढ़ा है। मोदी सरकार द्वारा तीन-तलाक और हज-सब्सिडी आदि पर जो पहल की गई उससे मुस्लिम महिलाओं और हाजियों में वह लोकप्रिय हुए हैं। कुछ मुस्लिमों के अनुसार मोदी की विकास योजनाएं सेक्युलर हैं जिनसे उनकी गरीब बेटियों को पढ़ने और आगे बढ़ने तथा मुस्लिम युवकों को स्व-रोजगार और स्व-व्यापार करने की प्रेरणा मिली। तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाएं मोदी की तरफ आशा से देख रही हैं. कई मुस्लिम युवतियों के अनुसार उनके परिवारों में तलाक ने उनकी चार-चार पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। उप्र जैसे बड़े राज्य में जहां 2004 और 2009 में केवल तीन प्रतिशत मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया वहीं 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा में यह नौ प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर भी 2014 लोकसभा में भाजपा को आठ प्रतिशत मुस्लिम मत मिले जो 2009 लोकसभा के मुकाबले दोगुने थे। यदि मौजूदा रुझान संकेतक हैं तो न केवल उप्र में, वरन देश के स्तर पर भी भाजपा के मुस्लिम मतों में लगभग तीन प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

अवधेश राजपूत

अक्सर आरोप लगते हैं कि मोदी ने कुछ किया ही नहीं, केवल जुमलेबाजी की। क्या वास्तव में मोदी ने पिछले पांच वर्षों में कुछ नहीं किया? पूर्वोत्तर-भारत को लीजिए। वहां लोगों को मोदी में विकास की नई रोशनी दिखी। परिणामस्वरूप 2016 से लगभग सभी राज्य असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा-भाजपा और सहयोगी दलों की झोली में आ गए। बंगाल, असम और त्रिपुरा जहां बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की गंभीर समस्या है वहां लोगों का मानना है कि बांग्लादेश से विवाद के बावजूद मोदी ने बांग्लादेश से मधुर संबंध बनाए हैं। अपने हितों की रक्षा करते हुए पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाये रखना मोदी के राजनीतिक कौशल को बताता है। मोदी के नेतृत्व को विश्व के सभी बड़े-छोटे देशों ने मान्यता दी है। प्रतिरक्षा हो या पर्यावरण, अर्थ हो या आतंक, मोदी की सीधी बात लोगों के दिलों में उतरती है, लेकिन मोदी सरकार की कमी रही है कि उनके मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने सरकार के कार्यों की मार्केटिंग ठीक से नहीं की।

चुनावों में दलों की सफलता का पैमाना उनका जनाधार होता है। मोदी ने भाजपा के जनाधार में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और शहरों में असंगठित क्षेत्र के गरीबों-मजदूरों को लक्ष्य किया है। अंतरिम बजट में किसानों को छह हजार रुपये प्रतिवर्ष और असंगठित मजदूरों को 60 वर्ष की आयु पर तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने से तमाम तबके लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना में मार्च 2019 तक लगभग तीन करोड़ लोगों के ई-कार्ड बन गए हैं और 17 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार के लिए डीबीटी वैसे ही 'गेम-चेंजर' सिद्ध होगी जैसे 2017 चुनावों में 'उज्ज्वला। डीबीटी के अंतर्गत अभी तक 55 मंत्रालयों की 439 स्कीमों द्वारा पूरे देश में लगभग सात लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण गरीबों और वंचितों को हो चुका है। यह तबका 'ओपिनियन-मेकर' तो नहीं, पर 'गवर्नमेंट-मेकर' जरूर हैं। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा-पत्र में अच्छे और लुभावने वायदे किए हैं पर ऐसे वायदे तो जनता 1950 से सुनती आ रही है। क्या वास्तव में जनता घोषणा-पत्रों को गंभीरता से लेती है? क्या वास्तव में वह उन वायदों के आधार पर मतदान करती है?

चुनावी वर्ष में प्रयागराज में आयोजित कुंभ के प्रभाव की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। कुंभ की दिव्यता और भव्यता तथा प्रशासनिक सुव्यवस्था के सकारात्मक राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सफाई कर्मचारियों के चरण पखारने और निषाद-मल्लाह समुदाय की खुशी के चलते निषाद-पार्टी सपा से नाता तोड़ भाजपा-गठबंधन में सम्मिलित हुई है। भारतीय मतदाता लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय नेतृत्व का महत्व समझ चुका है। उसके पास चयन के सीमित विकल्प हैं। सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता हाशिये पर हैं, लेकिन अपनी साफ-सुथरी छवि और कर्तव्य-निष्ठा के कारण मोदी सबसे अलग हैं। मोदी से असहमत होना, उनकी आलोचना करना विपक्ष का फर्ज है, लेकिन क्या उसके पास कोई बेहतर वैकल्पिक नीतियां और नेतृत्व है?

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

चुनाव बाद विदेश नीति का भविष्य

हर्ष वी पंत

मोदी सरकार की विदेश नीति बेजोड़ रही है, लेकिन क्या चुनाव बाद नई सरकार में इसकी निरंतरता कायम रहेगी?

भारत में चुनाव अभियान गति पकड़ रहा है। वैसे तो चुनाव में तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्दा ही सभी पर हावी है। वह जिन लोगों की आंखों में खटकते रहे हैं वे एक बार फिर उनके विरोध में लामबंद हो रहे हैं तो दूसरी ओर जो लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं वे उन्हें दोबारा सत्ता तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिशों में जुटे हैं, मगर इन चुनावों को दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। भारत में भले ही लोग मोदी को पसंद या नापसंद करें, लेकिन इस तथ्य को नहीं झुठलाया जा सकता कि उन्होंने भारतीय विदेश को ऐसी नई दिशा दी जो पहले कभी नहीं दी जा सकी। भारत को वैश्विक फलक पर आगे बढ़ाने में मोदी कितने प्रभावशाली रहे हैं, इसकी तुलना जवाहरलाल नेहरू से की जा सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एक नई आवाज दी है। यह आवाज भी पुराने भारत की आवाज से अलग है। इस तरह मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि पूरी दुनिया भारत की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर ध्यानपूर्वक गौर करे। वह वैश्विक जगत को आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सोचने के लिए उन्मुख करने में सफल रहे हैं। यह मसला भारत के लिए बेहद अहम रहा है। इसी तरह वह जलवायु परिवर्तन जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी भारत की संकोची किस्म की प्रतिक्रिया को भी भारतीय हितों के हिसाब से आत्मविश्वास के भाव से भरने में सक्षम रहे हैं। मोदी ने एक तरह अकेले अपने दम पर भारत की उस खोई जमीन को फिर से हासिल किया जो संप्रग के दूसरे कार्यकाल में नीतिगत पंगुता के कारण दरक गई थी। अगर किसी अन्य बात के लिए नहीं तो कम से कम इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ही उन्हें श्रेय दिया जा सकता है। पांच साल पहले दुनिया भारत से एक तरह नाउम्मीद सी हो गई थी, लेकिन वह भारत में फिर से संभावनाएं देखने लगी है। उम्मीद है कि भारत जमीनी स्तर पर कदम उठाकर इस मोर्चे पर खरा उतर सकता है।

चुनावी दौर में चर्चा मुख्य रूप से पाकिस्तान के इर्दगिर्द ही रहेगी, लेकिन मोदी की विदेश नीति व्यापक रूप से चीन के उभार से निपटने पर ही केंद्रित रही है। भारत जिन हकीकतों से दो-चार है उनमें चाहे कोई भी सरकार रहे, उसे चीन की चुनौती का तोड़ निकालने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। समय के साथ इसमें और तेजी आएगी। चुनाव के बाद चाहे जिसकी भी सरकार बने उसे चीन के उभार की चुनौती से निपटना ही होगा। चाहे भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में प्रवेश का मसला हो या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जैश ए मुहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने का प्रस्ताव हो, उनमें

चीन का लगातार अड़ंगा लगाकर यही दर्शाता आया है कि भारत के रणनीतिक परिदृश्य को वह कितने नाटकीय रूप से प्रभावित कर रहा है। चीन की पहेली सुलझाने में मोदी ने दक्षता दिखाई है। उन्होंने डोकलाम में चीन के खिलाफ डंटे रहने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआइ का दुनिया में सबसे पहले विरोध करने का दम दिखाया। इसके बाद उन्होंने वुहान में चीनी नेतृत्व से वार्ता भी की।

जब भारत अपने रणनीतिक परिदृश्य पर गौर करता है तो सत्ता में चाहे जो दल मौजूद हो तो उसके नेतृत्व के लिए चीन की चुनौती की अनदेखी आसान नहीं दिखती। बीते दो दशकों में समय से इसका आकलन न करने के कारण नई दिल्ली पहले ही काफी समय बर्बाद कर चुकी है। भारत इसे लेकर और लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरब और पश्चिम की ओर भारत के बढ़ते कदम मुख्य रूप से चीन की बढ़ती पैठ से निपटने का ही परिणाम हैं। इसके लिए उसे समान विचार वाले देशों के पूर्ण सहयोग की दरकार होगी।

मोदी ने पश्चिम विशेषकर अमेरिका को लेकर भारत की परंपरागत तटस्थता वाली नीति को तिलांजलि दी। अमेरिका के साथ उनकी सरकार की सक्रियता इसी विचार के साथ आगे बढ़ी कि भारत और अमेरिका अतीत की हिचक को पीछे छोड़कर आर्थिक-सामरिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह चीनी आक्रामकता को जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों की चौकड़ी का फिर से उभार भी इन देशों के नेताओं की उस हिचक को दूर करता है कि ऐसा करने से कहीं चीन कुपित न हो जाए। चीनी भावनाएं आहत करने वाली दलील अब व्यावहारिक नहीं रह गई है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आसियान पर जोर को लेकर मोदी इसी बात को अभिव्यक्त कर आसियान देशों की उसी चिंता को दूर करने की कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने सही रणनीति नहीं अपनाई तो उनका यह इलाका बड़ी शक्तियों के बीच खींचतान का अखाड़ा बन जाएगा। इस कड़ी में पूर्वी एवं दक्षिणपूर्वी एशिया के साथ भारत की सक्रियता बढ़ाने को लेकर वह भारत के पूर्वी पड़ोसियों के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव पर भी जोर देते हैं। जहां बंगाल की खाड़ी की ओर भारत अपने रणनीतिक भौगोलिक पहलुओं पर नए सिरे से विचार कर रहा है तो इससे पूर्वोत्तर भारत के माध्यम से दक्षिणपूर्व एशिया को निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकता है। इससे भारत के अनूठे भूगोल और दक्षिणपूर्व एशिया की वृद्धि की रफ्तार का लाभ उठाया जा सकता है। भारत के लिए अभी भी पश्चिमी हिंद महासागर सर्वाधिक महत्व वाला है। विशेषकर अमेरिका जैसी शक्तियों की तुलना में भारत के लिए इसकी कहीं अधिक अहमियत है। मोदी इस क्षेत्र में भारत की केंद्रीय भूमिका चाहते हैं। यह क्षेत्र उनके अनुसार अफ्रीका के तटों से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ है। पश्चिमी एशिया में भारत की गहरी होती पैठ और बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता के साथ ही दक्षिणपूर्व एशिया एवं अफ्रीका के बीच संपर्क बढ़ाने की कोशिशों से यह रणनीति जाहिर भी होती है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी की विदेश नीति बड़ी असरदार और गतिशील रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव नतीजों के बाद भी यह निरंतरता कायम रह सकती है? क्षमताओं में कमी और नतीजे देने को लेकर उठने वाले सवालों से भारत का जूझना जारी रह सकता है। अगर विदेश नीति में मौजूदा गतिशीलता को कायम रखना है तो नई सरकार को एकनिष्ठ होकर इन पहलुओं पर काम करना होगा।

(लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

नास्तिकता

प्रायः प्रत्येक बच्चा अपने शैशवकाल से ही खोजी प्रवृत्ति का होता है। कारण यह कि उसके चारों ओर चल रहा प्रकृति का रूपनर्तन उसके लिए कौतुकपूर्ण होता है, जिसमें बच्चा स्वयं को केंद्रीभूत पाता है। कदाचित रहस्यों की यही खोजी प्रवृत्ति ही मानव प्रगति का आधार रही है। बड़ा होते ही यही खोजी प्रवृत्ति उसके मन में स्थायी इच्छाओं और फिर नित नई महत्वाकांक्षाओं का रूप धर लेती है और वह संसार में स्थायी तृप्ति की चाह में आगे बढ़ता चला जाता है, किंतु अगर उसकी दृष्टि तीक्ष्ण हो तो उसे अंततः पता चल ही जाता है कि किसी भी महत्वाकांक्षा कि पूर्ति उसे तृप्ति नहीं दे सकती। कारण यह कि तृष्णा कभी पूरी नहीं होती।

एक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती कि मन दस नई महत्वाकांक्षाओं के महल खड़े करने में कुशल है। तब वह धर्म यानी परमात्मा की खोज में निकलता है जिससे उसे पूर्ण तृप्ति मिल सके। उस समय उसकी यहां वहां सिर मारती कामनाएं अमीप्सा और फिर मुमुक्षा का रूप धारण कर लेती हैं। भिन्न-भिन्न संप्रदायों के अलग-अलग भगवान हैं और वे सभी अपने-अपने भगवान को श्रेष्ठ साबित करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पता चलता है कि इस दुनिया में धर्म के नाम पर जितना खून बहा है उतना युद्धों में भी नहीं बहा है। तब उसके मन में एक नास्तिकता का जन्म होता है जिससे हम सकारात्मक नास्तिकता कहें तो बेहतर होगा। नास्तिकता का किन्हीं संप्रदायों से कोई सरोकार नहीं होता। जिस तरह महात्मा बुद्ध बारह वर्षों तक भटकते रहने के बाद संबोधि के क्षणों में तब पहुंचे जब उन्हें सारे धार्मिक कर्मकांडों की व्यर्थता का अहसास हुआ।

ऐसी नास्तिकता हमें धन्यता की ओर ले जाती है, जबकि दूसरी नास्तिकता ईश्वर के नकार की है जो ठीक वैसी है जैसे कि कोई अपनी आंखों की रोशनी खोकर सूरज के अस्तित्व को इन्कार करने की मूर्खता करे। कारण यह कि जिसके पास जरा भी आंख होगी, उसे उस परम ऊर्जा का थोड़ा बहुत अनुभव जरूर हो जाएगा, जिसके इशारे पर इस अखिल ब्रह्मांड का संचालन पूरी कुशलता से हो रहा है। इस प्रकार की नकारात्मक नास्तिकता का बाहुल्य पश्चिम में अधिक है।

रंजना गोंडवी

यौन शिक्षा की सख्त दरकार

देवेंद्रराज सुथार

यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि किशोर जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जान सकें

भारतीय समाज में यौनाचार को हमेशा से एक बेहद ही निजी मामला माना जाता रहा है। लोग यौनाचार को लेकर खुलकर चर्चा करने से कतराते हैं। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक मर्यादा का खयाल सताने लगता है। यौनाचार को लेकर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं होने के कारण ही इससे जुड़े अपराध एवं रोग जन्म लेते हैं। विदेशों में यौनाचार को लेकर कोई पर्दा नहीं है। वे खुलेआम यौनाचार की बातें करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए यौनाचार से जुड़े अपराध उन देशों में बेहद कम हैं। इसके विपरीत भारत में इसके बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करने वाले व्यक्ति को एक अलग निगाह से देखा जाता है। यहां तक कि हमारी संस्कृति में यौनाचार को जीवन की सफलता एवं मोक्ष के मार्ग में बाधक भी माना गया है। हालांकि यह और बात है कि यौनाचार को रहस्य का विषय बनाकर उससे जुड़ी भ्रांतियों के प्रति मौन रहने वाले देश में अजंता एलोरा, कोणार्क, खजुराहो जैसी कलाकृतियां भरी पड़ी हैं।

यौनाचार को एक बुराई के रूप में लेने से पहले हमें समझना होगा कि यह मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में विशेष स्थान रखता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैस्लो के मुताबिक भूख, प्यास और नींद के अलावा यौनाचार भी इंसान की प्रमुख शारीरिक आवश्यकताओं में से एक है। यौनाचार को जितना रहस्य बनाकर रखा जाएगा या इसका विरोध किया जाएगा उसके प्रति उतनी ही लालसा बढ़ती जाएगी। एक जैविक क्रिया के रूप में एक निश्चित उम्र के बाद यौनाचार अनिवार्य है।

लेकिन उम्र से पहले इन चीजों में बाल एवं युवा पीढ़ी की संलिप्तता उनके भटकाव का कारण भी बन सकती है। इसलिए हमें यौनाचार का विरोध करने के बजाय यह पता लगाना चाहिए कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी को उम्र से पहले यौनाचार की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इसका कारण इंटरनेट पर फैलाया जा रहा अश्लील वीडियो का जाल है जिसके शिकंजे में युवा पीढ़ी आसानी से फंस जा रही है। लिहाजा वह अपना ध्यान अध्ययन से हटाकर इन चीजों में लगाकर अपनी कामोत्तेजना को असमय जागृत करने लगी है। बहरहाल हालात दिनोंदिन विकट होते जा रहे हैं और इसके नकारात्मक परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पर रोक लगाने को लेकर कोई राजनीतिक मंशा नजर नहीं आ रही है।

दूसरा कारण है हमारे देश में यौन शिक्षा का अभाव होना, जिसके कारण इन चीजों में समय से पूर्व युवा वर्ग शीघ्र ही बहकता जा रहा है। इसे रोकने के लिए देश में यौन शिक्षा की सख्त आवश्यकता है। आज देश तीन गंभीर गलतियों से गुजर रहा हैं। एक तो बालक-बालिकाओं की कम उम्र में शादी से, दूसरा शादी के तुरंत बाद गर्भधारण से और तीसरा इस स्थिति को रोक पाने की अज्ञानता से। दुनिया में नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एवं फ्रांस जैसे देशों की तरह भारत में भी यौन शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए जिससे कि किशोर जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जान सकें। ऐसा होने से वे प्रजनन और यौन उत्पीड़न संबंधी आदि विषयों के प्रति जागरूक हो सकेंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

क्षेत्रीय दलों की हकीकत

नित नए राजनीतिक दलों का निर्माण शीर्षक से लिखे अपने लेख में राजीव सचान ने देश में छोटे-छोटे नए दलों के अस्तित्व में आने के कुछ कारणों का वर्णन किया है। धर्म, जाति और परिवारवाद को बढ़ावा देने में सिर्फ क्षेत्रीय दलों का ही हाथ नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय दल भी इसमें बराबर के भागीदार हैं। राष्ट्रीय दल वोट के खातिर उन क्षेत्रीय दलों से भी हाथ मिलाने में देरी नहीं करते जिनका जन्म ही किसी धर्म या जाति के आधार पर हुआ होता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की यही सोच है कि हमारे देश के लोग बहुत जल्दी और आसानी से धर्म-जाति की भावनाओं में वहक जाते हैं। यह सच भी है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो देश और जनहित के मुद्दों के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म-जाति के आधार पर अपने कीमती वोट का प्रयोग करते हैं। यहां यह कहना भी उचित होगा कि अपने समाज के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए और अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जब इसका प्रयोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जाने लगे तो यह जरूर गलत है। इससे लोकतंत्र की जड़ें निश्चित रूप से कमजोर होती हैं। दुर्भाग्य से देश में ऐसे नेताओं की संख्या लगातर बढ़ रही है। चुनाव आयोग को ऐसे अवसरवादी नेताओं पर लगाम लगाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। यहां यह भी कहना उचित होगा कि कुछ लोगों ने राजनीति को कालेधन को सफेद करने का जरिया बना दिया है। जाहिर है देश में छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व में आने का एक कारण कालेधन को खपाना भी हो सकता है।

raju09023693142@yahoo.com

मेलबाक्स

राजनीति में वंशवाद

दैनिक जागरण के 04 अप्रैल के अंक में प्रदीप सिंह का लेख, नेता पुत्रों का राजनीतिक भविष्य, पढ़ा। इसमें वंशवादी पार्टियों का सटीक विश्लेषण किया है। उनका यह कहना अक्षरशः सही है कि वंशवादी पार्टियों का भविष्य उनकी भावी पीढ़ी की क्षमता एवं योग्यता पर निर्भर करता है। वंशवाद की अवधारणा राजतंत्र की देन है। राजतंत्र में राजा का बेटा ही उसका उतराधिकारी होता था, किंतु इतिहास साक्षी है कि जब भी कोई अक्षम उतराधिकारी आया तो राज्य नष्ट हो गया। वर्तमान राजनीति में सपा, बसपा, इनेलो, राजद, तेलुगु देसम आदि कई पार्टियां वंशवाद की बेल को ही आगे बढ़ा रही हैं। यदि इनकी पीढ़ी असफल होती है तो ये वंशवादी पार्टियां इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगी। बेशक कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अब तो वह भी पूरी तरह एक ही परिवार के प्रति निष्ठावान है। परिवार के मोहजाल में फंसी कांग्रेस जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री एवं इंदिरा गांधी की विरासत को संभाल नहीं पाई। इंदिरा गांधी के असामयिक निधन के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। यहीं से कांग्रेस में वंशवाद की बेल विकसित हुई। सोनिया गांधी स्वयं प्रधानमंत्री बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं, लेकिन कांग्रेस पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। कांग्रेस में परिवार के अतिरिक्त कोई सक्षम नेतृत्व उभर ही नहीं सका। अब राहुल गांधी पर कांग्रेस की आशाएं टिकी हैं। कांग्रेस पुरानी पार्टी है उसे इस पर मंथन करना चाहिए। व्यक्तिनिष्ठ एवं परिवार निष्ठ पार्टियों का अस्तित्व तभी तक कायम है जब तक उनके पास सक्षम नेतृत्व है।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

चीन की धूर्तता

चीन एक तरफ मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के लिए अमेरिका सहित अन्य देशों के कार्रवाई पर वीटो कर देता है। दूसरी तरफ दुनिया को ये बताने की कोशिश करता है कि वह मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है। चीन की चालाकी का आकलन उसकी बातों से बड़े आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उसकी इस चालाकी को सभी देश समझ नहीं पा रहे हैं। अगर देखा जाए तो चीन की धूर्तता पाक से भी कहीं ज्यादा है। वह अपनी मीठी बातों से अपनी तरफ आकर्षित तो कर लेता है, लेकिन विश्वासघात करना नहीं भूलता। चीन को इतना तो पता है कि मसूद अजहर कितना खूंखार आतंकी है फिर भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाने के लिए वह संयुक्त राष्ट्र के उन 14 देशों के जज्बातों को दरकिनार कर देता है जो भारत के साथ खड़े हैं।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।